ज्ञानातिक व्यवस्था में जनादेश का समझाने में हुई चूकों की भारी कीमत समझाने में हुई चूकों की भारी कीमत समझाने में हुई चूकों की भारी कीमत तब और बढ़ जाती है जब ऐसी चूकें जान-बूझकर की जाती है। कई राजनैतिक दल लोगों को भरमाने और अपने राजनैतिक प्रमात्त्व के लिए ऐसी चूकें जान-बूझकर करते हैं। मूल बात यह है कि जनतंत्र में प्राप्त वात यह है कि जनतंत्र में प्राप्त जात यह है कि जनतंत्र में प्राप्त जात राजकिश कभी भी निःशत तहीं होता होगा। जनादेश की भी निःशत नहीं होता होगा। जनादेश की शतें संविधान तय करता है। आजकल भारतीय जनतंत्र में जनादेश की अवहेलना करती हुई लगती हैं। जनतंत्र के लिएए- राजनैतिक और सामाजिक दृष्टि से भी- यह अशूभ लक्षण है।

अनुवाद न होकर आंतरिक उपनिवेश से। मुक्ति के लिए हुए लंबे सामाजिक संघर्ष से मुक्ति और आधुनिक भारतीय राष्ट्र के गठन के लिए हुए जनसंघर्ष तक है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि जनतंत्र में चुनाव से प्राप्त जनादेश मूलत: अस्थायी ही होता है। इस अस्थायी जनादेश के कई प्राप्त एक भारतीय अनुभव भी है। इस 本 सांस्कृतिक और सामाजिक पाठ को लेकर है। यह चिता इसलिए है कि सांस्कृतिक गुजरात का यह चुनाव सामान्य परिस्थिति राजनैतिक अंतर्वस्तु के लगभग पूर्ण धुवीकरण से उत्पन्न हुई है। विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच संबंधों के अलावा पहलू सामाजिक विन्यास के गैर-सवर्ण और सवर्ण पक्ष से भी जुड़ता है। वस्तुत: भारतीय सामाजिकताओं में धर्मनिरपेक्षता और संप्रदायवाद का ऐतिहासिक द्रंद्र रहा है। धर्मनिरपेक्षता सिर्फ 'सेकुलरिज्म' का प्रभाव चिरस्थायी होते हैं। गुजरात के जनादेश को पढ़ने में होने वाली चुक का खमियाजा देश को स्थायी रूप से भोगना पड सकता है। गुजरात के जनादेश का एक पाठ राजनैतिक है, तो दूसरा पाठ सांस्कृतिक अपने हित साधन के लिए इसका राजनैतिक पाठ तैयार कर रहे हैं। चिंता इस जनादेश के और सामाजिक ढांचों और अंतर्वस्तु पर गुजरात के जनादेश का स्थायी प्रभाव आशंकित है। ध्यान में खबना होगा कि में नहीं हुआ है। यह असामान्य परिस्थिति धर्मनिर्पेक्षता और संप्रदायवाद की उपलब्ध धर्मनिरपेक्षता और संप्रदायवाद का एक है। राजनैतिक दल उपनिवेश अनुभव का विस्तार बाहरी और सामाजिक भी

राजसता पर इस्लाम को मानने वालों के आरोहण के बाद इस द्वंद्र में नए आयाम और नई तीव्रता का जुडाव हुआ था। धर्मनिरोक्षता की चुनौती के रूप में इस नए आयाम का संदर्भ हिंदू-मुसलमान के

सामाजिक बरताव के लिए मानवीय आधार की तलाश से बनता है। धर्म पर से एकतान संघषिशील गैर-सवर्ण चेतना के बड़े भाग के संप्रदायवाद के पक्ष में चले जाने से यह धुवीकरण बना। सवर्ण चेतना के राजनैतिक रथ में गैर-सवर्ण चेतना के राजनैतिक नेतृत्व के बार-बार विकल्प के बनने का काम बड़ा अंश सवर्ण मनोभावों से निर्मित है। हिंदू-मुसलमान संबंधों में मधुरता के लिए 'राम' और 'रहीम' के एक होने की बात बन पाई। आज भी हिंदू-मुसलमान के बीच कटुता बढ़ाने वालों में सवर्ण सिक्रियता अलिक्षित नहीं है। क्या यह महज एकतानता भी है? गुजरात के इस चुनाव में धर्मनिरपेक्षता के लिए ऐतिहासिक रूप जुत जाने से भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष संखना को बचाने वाले प्रभावी और आधारित भारतीय समाज की संरचना का पहले भी कभी सबर्ण चेतना का अंग नहीं संयोग है? या इसके पीछे सिक्रिय सामाजिक-आर्थिक संरचना के यथार्थ की वास्तिविक

द्विराष्ट्रीयता के जन्म के समय 'दलित राष्ट्र' जैसी अवधारणा भी प्रकट हुई थी। सामाजिक पाठ तैयार नहीं हो सकता। ध्यानै में यह भी खना होगा कि गुजरात के जनादेश के बाद ही तेजी से 'हिंदू राष्ट्र' को राजनैतिक अवधारणा के तोड़ के रूप लिए संयुक्त निर्वाचक मंडल बने रहे और दलितों के 'दलित राष्ट्र' की अवधारणा को स्थिगित करवाने में उस समय सफलता मिली थी। यह सफलता इसलिए मिली थी कि धर्मनिस्पेक्षता और सामाजिक न्याय के मैकडोनल्ड प्रस्ताव में दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के मुद्दे पर गांधी जी के आमरण अनशन के कारण एक नुणे समझौता हुआ था। इस समझौते के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की मुश्किल होता जा रहा है। **द्रा**न जटिलताओं को ठीक से समझे **द्र** बिना गुजरात के जनादेश का में दलित राष्ट्र की अवधारणा फिर उभर रही है। इतिहास की ओर नजर डालें तो सामाजिक तक भरोसा करने के काबिल मानने का अवसर बचा हुआ था। याद किया जाना चाहिए कि सांप्रदायिक मामले में अगस्त १९३२ के 48 जाने आश्वासन प्रतिफलन को परखे अनुसार हिंदुओं राजनैतिक

गई। यह ब्यवस्था आज भी लागू है। सामाजिक न्याय के आश्वासन को ब आस्था के प्रावधानों से ही सीमित कर में देना सामाजिक न्याय की मानवीय से आकांक्षा को भ्रमित करने वाला साबित है

प्रफुल्ल कालख्यान

होगा, कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा। हिंदू वर्णाश्रम व्यवस्था बन जाएगी, जिसके अंतर्गत समाज चार भागों में विभाजित धर्म के समग्र अंग के लिए प्रत्येक भाग समान रूप से आवश्यक होगा या एक भाग उतना ही आवश्यक होगा जितना संदर्भों को वे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। आंबेडकर ने तब बहुत व्यथा के साथ साप्ताहिक 'हरिजन' के लिए संदेश देने से असल में यह तथ्य तब भी अलक्षित नहीं था कि 'वर्णव्यवस्था' जन्म के लिए के अनुसार शुद्ध हो जाएगी। यह सच्ची होगा और प्रत्येक भाग एक दूसरे का पूरक दूसरा।' उनका विचार 'अस्पृश्यता' के खत्म होने पर टिका हुआ था, लेकिन इस अस्पृश्यता के खत्म होने के आर्थिक का उद्धार संभव नहीं है।' इस उद्धार का आधार नहीं बन सकते थे। सामाजिक अन्याय को संभव बनाने वाली सामाजिक प्रथा भी शुद्ध हो जाएगी, अर्थात मेरे स्वप्नों इस आधार पर मना कर दिया था कि सामाजिकताओं पर पड़ा है। बाद के दिनों आपातकालीन राहत न मानकर इसे बोट की से ही देखा गया। आरक्षण के के लिए तो कुछ हद तक कारगर हो सकते थे, क्षति की प्रक्रिया को समाप्त करने का अतिरिक्त प्रयास अपेक्षित थे। ये प्रयास नहीं किए गए। इसकी आशंका तब भी सामाजिक सुधार तक ही सीमित था। उस सामाजिक सुधार में आर्थिक मांगों के लिए कोई जगह नहीं थी। इसके साथ ही गांधी जी ने समग्र रूप में जाति-व्यवस्था का विरोध नहीं किया। १९२६ में प्रकाशित 'वणािश्रम धर्म' में व्यक्त उनके विचार थे, "अस्पुश्यता जैसे ही खत्म होगी, स्वयं जाति जाति-व्यवस्था को नष्ट किए बना अछूतो आशय सामाजिक और आर्थिक दोनों था। व्यक्त की गई थी। गांधीजी जी का प्रयास प्रावधान सामाजिक अन्याय की क्षतिपूर्ति को समाप्त करने

आधार पर ही सही, अम-विभाजन का नहीं, सांप्रदायिक दिखने वाला यह धुवीक अमिक-विभाजन का ही आधार कर्नती है। अपने केंद्रीय बनाव में प्रदेशवाद के विष बावजुद इसके राज्य के अंतःकरण में से भी प्रस्त रहा है। इस पर विचार कि धर्मनिरपेक्षता के बसाव का आग्रह बने जाना चाहिए कि संप्रदायवादी धृवीकरण रहने तक सामाजिक न्याय के भी देर-संबर लिए सवर्ण चेतना और प्रदेशव हासिल होने की संभावना में कुछ जान धृवीकरण के लिए गैर-सवर्ण चेतना में कित मंगे हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के सिक्रय होने योगदान रहा है। प्रसंगवसा, शिव सेना से सामाजिक न्याय पूर्णतः अपक्षित हो गया राजनैतिक उभार में 'हिंदुत्व' और 'मर, से सामाजिक अन्याय की बुनियाद अस्मिता' के मिन्नण को सिक्रय बनाने तो इसी हिंदू व्यवस्था के सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिय को भी याद किया

जुड़ी तीन प्रवाह का उठान मार रहा है। 'गुजरात' को अगर पूरे भारत में उठाने का प्रयास किया जाएगा तो आचरण में मौजूद रही है। आंबेडकर ने 'क्रांति और प्रतिक्रांति' में भारतीय वाली हैं। यह हिंदू भारत आत्म-विखंडन बनने की दिशा में बढ़ने के रास्ते का सबसे बड़ा अवरोधक रहा है। यह अवरोध आज उसके सामाजिक पाठ को इस हंग से कम खतरनाक साबित नहीं होगी। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा हो या उसकी प्रतिनिर्मिति 'दलित राष्ट्र' की अवधारणा, दोनों ही आत्मविभक्त भारतीय सामाजिकता की दरार को अधिक चौड़ा और तीखा बनाने से लहुल्हान भारतीय सामाजिकता के एक सामाजिकताओं के संदर्भ में कहा था कि भारत में 'ब्राह्मण भारत', 'हिंदू भारत' अस्तित्व रहा है। वर्णव्यवस्था के कारण भारत की सामाजिकता आत्मविभक्त रही है। ऐसे में दलित राष्ट्र की अवधारणा भी संस्कृतियों की त्रिधाराओं के है। इनसे अलग-अलग रहे

द्भास चुनाव में गुजरात की आस्पेता की स्वात बहुत जोरदार ढंग से उठाई गई। इस 'अस्मिता तत्त्व' की अनदेखी करने से हम 'भारतीय अस्मिता' से अलग और भिन्न मोदी को बहुत ताकतवर और अपने दल की केंद्रीय नीति से टकराते हुए चलने वाली ही नहीं, भारतीय संघ की संवैधानिक संस्थाओं और बुनियादी मान्यताओं से भी प्रतीक नेता के रूप में सफलतापूर्वक उभारा। केशु भाई पटेल के सामने विनीत होने और हिरेन पांड्या के मामले में अपने दल के केंद्रीय हस्तक्षेप को दृढ़तापूर्वक लिए सवर्ण चेतना और प्रदेशवादी धुवीकरण के लिए गैर-सवर्ण चेतना के पहचान पर आधारित होने की आकांक्षा से परहेज नहीं है। ध्यान में रखना चाहिए कि सांप्रदायिक दिखने वाला यह धुवीकरण अपने केंद्रीय बनाव में प्रदेशवाद के विषाणु जाना चाहिए कि संप्रदायवादी धुवीकरण के योगदान रहा है। प्रसंगवश, शिव सेना के किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र निरंतर टकराने बाली 'गुजराती अस्मिता' के नकारने की प्रतीति कराकर नेंद्र मीदी को गुजराती अस्मिता' का प्रतीक बनाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही। ऊपर से से भी ग्रस्त रहा है। इस पर विचार किया संगठन का इस ध्रुबीकरण में कितना राजनैतिक उभार में 'हिंदुत्व' और 'मराठी अस्मिता ' के मिश्रण को सिक्रय बनाने की घनघोर प्रादेशिकता स्वतः समाहित भटक सकते हैं। इस अस्मिता तत्त्व क्योंकि इस 'गुजराती अस्मिता'

सकता है। कांग्रेस इस प्रदेशवाद के मर्म को ठीक से समझ ही नहीं पाई। कांग्रेस अपने सांगठिनक ढांचे के अतिकेंद्रित होने के कारण इसे समझकर भी कुछ कर पाने की स्थित में शायद ही हो पाती।

संस्कृति की कृत्सित समझ से उत्पत्र 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' के निहित आशय के आधार पर किए जाने वाले कार्यों से भारतीय सामाजिकताओं में नागरिकों के संघात्मकता हमारे राजनैतिक गठन का अनिवार्य अंग है। दुखद यह है कि अपर से संघात्मकता की ओर बढ़ती दिखने है। राजनैतिक गठन के संघहीन होते जाने से बने वातीवरण में सामाजिक संघात एकात्मकता और संघात्मकता को संवादी बनाए रखने में बहुत हद तक कामयाब रहे दिनों में कांग्रेस राजनैतिक प्रासंगिकता के शिखर पर रही है। लेकिन सांगठनिक हांचा भारतीय राज्य की बुनियाद में संघहीनता के प्रदूषण के प्रवेश को रोक पाने में पूरी तरह से सक्षम कांग्रेस के गिर जाने से उपजी राजनैतिक शून्यता को भर पाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे वैकल्पिक सांगठीनक ढांचे को की ओर ही तेजी से बढ़ती है। जैसे धर्म के फैलती है, वैसे ही संघात्मकता के नाम पर जरूरत है जो अपने आंतरिक गठन में बीच का सामाजिक संतुलन और भारतीय नाम पर संप्रदायवाद से उत्पन्न धर्महीनता प्रदेशवाद से उत्पन्न संघहीनता फैल सकती राज्यों में एकात्मकता और संघात्मकता का राजनैतिक संतुलन बिगड़ रहा है। वाली यह गत्यात्मकता भीतर से संघहीनता और अधिक जानलेवा साबित होगा एकात्मक भी हो और संघात्मक भी हो। नहीं दिखता। अप्रासंगिकता के गर्त अतिकेंद्रित इस धुवीकरण के संकेत कांग्रेस का

समझना जरूरी होगा।

ज्जा गुजरात में प्रदेशवाद के सहारे हुआ राष्ट्रवाद के सहारे दुहराया जा सकता है। इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बीज 'संप्रदायवाद' के मिश्रण से तैयार रासायनिक खाद से अंखुआते हैं। इस चुनांव के प्रचाद से अंखुआते हैं। इस चुनांव के प्रचार के दीरान प्रदेशवाद को निर्मित करने में 'राष्ट्रवाद' की भी कम मदद नहीं ली गई। अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में अग्र और अंध राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय संदर्भ में अग्र और अंध राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय संदर्भ में अग्र और अंध राष्ट्रवाद के राजनीतिक चारित के ह्य में विकसित करने के 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' के खतरनाक इरादे को ठीक से पढ़ना जरूरी है। यह सच्च है कि पूरा भारत गुजरात नहीं है, लेकिन यह ध्यान में रखना ही होगा कि गुजरात भी भारत में ही है।